राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

राष्ट्रीय जनता दल का मासिक मुखपत्र

अंक–41 जुलाई, 2025 सहयोग राशि–40 रुपये

इस बार

तेजस्वी : दलितों की पहली पसंद– लारैब अकरम/साकिब अशरफी	03
मनाया गया राजद का 29वां स्थापना दिवस– डॉ. दिनेश पाल	06
जनता की परिक्रमा करनेवाले ही होंगे उम्मीदवार– तेजस्वी प्र. यादव	10
राजद का राजनीतिक नीति से संबंधित प्रस्ताव	15
सामाजिक न्याय, जाति जनगणना एवं आरक्षण नीति संबंधी प्रस्ताव	16
राजद का आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव	18
राजद का विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव	20
वोटबंदी के खिलाफ महागठबंधन का बिहार बंद– मुकुंद सिंह	21
सरकार और बिहार दोनों को बदलना है– राहुल रॉय	23
यादों के झरोखों से– अब्दुल कादिर	24
दिव्यांग आंदोलन को मिली नई ताकत– अमृतेश कुमार मिश्रा	25
सामाजिक-राजनीतिक मसले	
नागरिकता सत्यापन चुनाव आयोग का काम नहीं– रवीश कुमार	26
पत्रकारों का काम सरकार की नींद हराम करना है– नेहा सिंह राठौर	29
नियुक्तियां स्याही नहीं तनख्वाह में बोलती हैं– कंचना यादव	30
संघर्ष को अपराध के चश्में से नहीं देखें– डॉ. अनुज कुमार तरुण	31
भाजपा सरकार की नाकामियों के 11 साल– डॉ. अमित रंजन	33
पठन-पाठन	
समाजवादी राजनीति का लेखा-जोखा पेश करती पुस्तक– शिवदयाल	36
कवि का पन्ना– एन.के. नंदा की कविताएं	40

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

लारैब अकरम/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी

मंगनीलाल मंडल

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com

गहन मतदाता पुनरीक्षण : चुनाव चोरी का षड्यंत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन का जो फरमान पिछले माह जारी किया गया था उसके एक माह पूरा होनेवाला है। लेकिन आयोग के इस निर्णय के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा। विभिन्न पार्टियों, संगठनों और नागरिक मंचों द्वारा लगातार इसका विरोध जारी है। चुनाव आयोग ने इतनी कम अवधि में इस सर्वे के लिए जो प्रक्रिया अपनाया है, उसपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन पूरे सवालों पर निर्वाचन आयोग ने जिस तरह की चुप्पी साध रखी है, वह इस बात को इंगित करता है कि आयोग पूरी तरह सत्ताधारी पार्टी भाजपा की गिरफ्त में आ गया है। 76 वर्षों के भारत के संसदीय इतिहास में मोटेतौर पर अबतक एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की शाख बरकार थी, लेकिन हाल के वर्षों में अलग-अलग राज्यों में चुनाव आयोग की जैसी भूमिका रही है, उससे उसके स्वायत संस्था होने का नकाब उतर गया है और वह पूरी तरह से मोदी सरकार की हुक्मउदुली कर रहा है। बिहार में गहन पुनरीक्षण का कार्य, जो पूरे देश में प्रस्तावित है, व्यापक गरीब, वंचितों को मताधिकार से वंचित कर चुनाव चोरी करने का षड्यंत्र है।

बिहार में बी.एल.ओ के ऊपर इतनी कम अवधि में इस सर्वे को जिस तरह से निबटाने का दवाब है, संभव है उसमें बिहार में करोड़ों वोटर मतदान से वंचित हो जाएं। कोर्ट से बचने के लिए आयोग भले ही अपने वायदे की खानापूर्ति कर ले, लेकिन सच तो यही है कि इतनी कम अवधि में यह काम संभव ही नहीं है। इस सर्वे में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जो जमीनी हकीकत सामने आयी है, वह चौंकाने वाली है। कहीं सैकड़ों फार्म गंगा ओवरब्रीज पर गिरते दिखलाई पड़ रहे हैं, तो कहीं-कहीं दो तरह के फार्म नजर आ रहे हैं। सर्वे को जल्द संपन्न करने के चक्कर में गांव गये बगैर ही लोगों का फार्म बी.एल.ओ भर दे रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जिस बात की सबसे अधिक अनदेखी की गई है वह यह है कि मतदाताओं को दो फार्म देने की बात कही जा रही थी, वह लगभग

कहीं नहीं दी गई। इस पूरे प्रसंग का सच कई तरह के विभ्रम पैदा कर रहे हैं। बिहार के ज्यादातर मतदाताओं को फार्म नहीं मिले, बड़ी संख्या में ये फार्म बिना दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर के भरे गए। पलायन के कारण बिहार में बड़ी संख्या में बाहर गए लोगों में जिस तरह की अफरा-तफरी का माहौल पैदा हुआ, उससे बिहार के पूरे ग्रामीण हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्रमाण पत्र के लिए आफिसों का चक्कर लगा रहे हैं। यह आशंका उन्हें लगातार जीने नहीं दे रही कि अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं होता है तो मिलनेवाली सरकारी सुविधाओं से वे महरूम हो जाएंगे। सवाल है कि ऐसी अफरा-तफरी का जो खेल पूरे बिहार में चल रहा है, क्या सचमुच करोड़ों लोग वोट से वंचित कर दिये जाएंगे?

यह सवाल भी लगातार सामने आ रहे हैं कि आयोग का काम पारदर्शी चुनाव कराना है या नागरिकता सत्यापित करना, यह भी कि अगर यह मतदाता सूची इतनी ही संदिग्ध है तो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव सम्पन्न हुआ, उसको फिर किस तर्क के साथ वैध माना जाये, ये और इस तरह के ढेर सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिनका जवाब न चुनाव आयोग के पास है, न भाजपा, एनडीए और मीडिया के पास है। केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने मॉनसून सत्र में निर्वाचन आयोग के इस कदम का तीखा प्रतिवाद किया है। विपक्ष का आरोप आयोग की पूरी प्रक्रिया से है, जो काम दो साल में होता, उसे एक माह में कराने का सीधा अर्थ सरकार की महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर अपनाई गई रणनीति है। भाजपा की अपनी ही सहयोगी टीडीपी ने इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की है, वह तो और भी तल्ख है और इस बात का सबूत भी कि निर्वाचन आयोग अपने दायित्वों से किस तरह विमुख होकर काम कर रहा है। इन स्थितियों के उलट बिहार में मीडिया ने जिस तरह के भ्रम की स्थिति पैदा किया है, वह बेहद डरावना है। आयोग के सर्वे का यह काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और पता नहीं किन सूत्रों के हवाले से यह खबर छप गई कि 'बिहार में 35 लाख लोगों का नाम कटना तय है।' जिन 35 लाख लोगों को ये अखबार घुसपैठिये बतला रहे हैं, इस सर्वेक्षण कार्य में भाजपा के हजारों की संख्या में लगे किसी बी.एल.ए को बिहार में विदेशी घुसपैठिये नहीं मिले, चुनाव आयोग के किसी प्रेस नोट में घुसपैठिये की कोई चर्चा नहीं की गई तो सवाल उठता है कि इन अखबारों को किन सूत्रों के हवाले से इतना बड़ा तथ्य हासिल हो गया कि बिहार से 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिये गए अपने 7 सौ पृष्ठों के हलफनामे में कहीं भी इस आशय का जिक्र तक नहीं किया है, तो यह खबर आखिर किस स्रोत के आधार पर छापी गई, और अगर छापी गई तो उसकी पुष्टि या खंडन चुनाव आयोग की ओर से क्यों नहीं किया गया, यह सब इसलिए नहीं किया गया कि आयोग, मीडिया और भाजपा का यह एक नापाक नेक्सस है, जो इसी तरह लोगों को बरगलाये रखना चाहता है ताकि भाजपा के हिन्दू राष्ट्र का यह अभियान इसी तरह आम आदमी की कीमत पर परवान चढ़ता रहे। बिहार के अखबारों ने चुनाव आयोग के इस अभियान की कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, न आम आदमी के ऊपर आनेवाली परेशानियों का सच रखा, वह केवल और केवल भाजपा और चुनाव आयोग का एजेंट बनी रही। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम को वह आम आदमी के नजरिये से नहीं बल्कि भाजपा के एजेंडे का हिस्सा होकर चित्रित करती रही है। मीडिया की इस भूमिका पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़ी टिप्पणी की है। सूत्रों के हवाले से को उन्होंने मूत्रों की संज्ञा तक दे डाली जिसको लेकर पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। काश! उनका यह आक्रोश उन्हें खुद के अंदर आत्मावलोकन की प्रेरणा दे पाता। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिन्दी मीडिया में जिन सवर्ण हिन्दूवादी मर्दों का कब्जा है उन्होंने कभी अपने अंदर आत्मावलोकन की तमीज ही पैदा नहीं होने दी, तो आज अचानक उनके अंदर यह शऊर कहां से पैदा हो जाएगा?

मीडिया की जब भी बात की जाती है, अक्सर लोग उसके क्षरण के लिए आज के समय को दोष देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह मीडिया औपनिवेशिक दौर में भी निरपेक्ष नहीं रहा है। अगर यह निरपेक्ष रही होती तो अपने समय में गांधी, अम्बेडकर, नेहरू, लोहिया, जगदेव प्रसाद, किशन पटनायक और रामअवधेश सिंह को अपनी-अपनी पत्रिकाएं क्यों निकालनी पड़ती? सच तो यह है कि हिन्दी मीडिया अपने शुरूआती दौर से ही जातीय, लैंगिक और नस्लीय पूर्वाग्रहों का पृष्ठपोषण करती रही है। इतिहास के लंबे दौर को देखें तो हर वह घटना जो इस देश के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों से जुड़ा हो, उसको नकारात्मक फ्रेम में अंकित करना हिन्दी मीडिया का मुख्य चरित्र रहा है। इसलिए समय का तकाजा है कि हम इस मनुवादी मीडिया के मायाजाल से बाहर निकलें, और अपनी पत्रकारिता स्वयं करें।

गहन मतदाता पुनरीक्षण पर पटना से दिल्ली तक विपक्षी दलों की व्यापक गोलबंदी इस बात का संकेतक है कि भारत की महान आवाम लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के इस हमले को नाकाम करेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की यह बयान कि उन्होंने चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला रखा है, इस आसन्न खतरे की गंभीरतो को दर्शाता है।

अरुण आनंद